(a) whether M.T.N.L. procured l0020 subscriber Loop Carrier (SLC) System and 131 racks during 1989—93 worth Rs. 764 Lakhs;

(b) number of SLCs and racks lying idle and un-utilized as on date;

(c) reasons for the non-installaction of them so far and future plans to utilise the same; and

(d) name of the suppliers?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI KABINDRA PURKAYASTHA): (a) Yes, Sir.

M.T.N.L. ordered and procured in different lots 100.20 subscriber Loop Carrier Systems which were house in 153 racks at a total cost of Rs. 767 lakhs during 1989—93, out of which 1200 SLC Systems housed in 25 racks were diverted to Karnataka Telecom. Circle during 1995-96.

(b) 5291 Nos. of SLC Systems housed in 66 racks were not put to use and are laying unutilised.

The SLC Systems are used to install telepones in TNF areas as a temporary measure, till cable paris are made available by way of laying additional underground cables As Cable pairs provision is a dynamic process, the utilisation of SLC also keep varying. Some of the SLC Systems were not giving satisractory service and has gone faulty. It is being examined whether the systems can be repaired economically. In case it is not possible to repair them at reasonable cost the Systems will be scrapped.

(d) 3 Suppliers namely M/s. NATELCO, M/s. HFCL and M/s. Mekaster supplied these items.

Extension of Beat in MA 34 Section from Nagercoil to Madural

2932. SHRI N. THALAVAI SUNDARAM: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether any steps are being taken in regard to extension of beat in MA 34 section from Nagercoil to Madurai (mail service) by Chief Post Master General, Tamil Nadu;

(b) whether as per the reply by the Chief Post Master General, Tamil Nadu, the papers are pending before Delhi Office;

(c) if so, the reasons for the delay; and

(d) how long it will take for extension of beat in MA 34 section from Nagercoil to Madurai?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI KABINDRA PURKAYASTHA): (a) Yes, Sir.

Necessary orders were issued for extension of the beat of MA 34 Section from Nagarcoil to Madurai on 15.5.1998 and the said orders implemented by Tamil Nadu Circle with effect from 1st July, 1998.

(b) to (d) Do not arise in view of (a) above.

Shifting of Chief General Manager's Office

2933. SHRI SHARIEF-UD-DIN SHARIQ: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Chief General Manager has shifted his office from Srinagar to Jammu because of growing militant activities in this State;

(b) whether there is scene of normalcy after shifting;

(c) whether the office of the said office bearer is to be brought back at its original place; and

(d) if so, by when?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI KABINDRA PURKAYASTHA): (a) Yes, Sir. The Chief General Manager

has established a camp office at Jammu due to growing militant activities in Kashmir Velley.

(b) Chief General Manager is performing his duties of operation & maintenance of Telecom. Services in J & K.

(c) and (d) At present it is proposed to continue the camp office at Jammu.

डाक और तार सेवाओं में निजी क्षेत्र की भागीदारी

2934. **श्री गोविन्दराम मिरी:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार ने डाक और तार सेवाओं में निजी क्षेत्र की भागीदारी की किस सीमा तक आमंत्रित की अपेक्षा शहरी क्षेत्रों में सेवाएं प्रदान करने में अधिक रूचि दिखाई है,

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण है, और

(घ) ग्रामीण क्षेत्रों में इन सेवाओं को और सुदृढ़ के लिए सरकार की अद्यतन योजना क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कवीन्द्र पुरकायस्थ):

डाक विभाग (क) सरकार ने डाक सेवाएं प्रदान करने में निजी क्षेत्रों की सहभागिता आमंत्रित नहीं की है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

दूरसंचार विभाग:

(क) से (ग) सरकार ने बुनियादी टेलीफोन सेवाएं प्रदान करने के लिए 21 दूरसंचार सर्किलों में नीजि क्षेत्र की सहभागिता आमंत्रित की है। इनमें से छह कंपनियों ने छह सर्किलों के लिए पहले ही लाइसेंस करार पर हस्ताक्षर कर दिये हैं। जहां तक मूल्यवर्धित सेवाओं का संबंध है, यह उल्लेख किया जाता है कि चार महानगरों में सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा के प्रचालन के लिए 8 लाइसेंसधारक कंपनियों को 8 लाइसेंस दिये गये हैं तथा 8 क्षेत्रीय दूरसंचार सर्किलों के लिए 14 कंपनियों को 34 लाइसेंस प्रदान किये गये हैं। 54 शहरों में पब्लिक मोबाइल रेडियों ट्रंक सेवा के प्रचालन के लिए 25 कंपनियों को, ई-मेल के प्रचालन के लिए 15 कंपनियों को, वायस मेल /ऑडियों टेक्स सेवा के प्रचालन के लिए 14 कंपनियों को तथा इनसेट उपग्रहों के माध्यम से 64 केबीपीएस क्लोज्ड यूजर ग्रुप डामेस्टिक डाटा वी-सेट सेवा के प्रचालन के लिए 12 कंपनियों को लाइसेंस दिये गए हैं। रेडियों पेंजिग सेवा के संबंध में यह उल्लेख किया जाता है कि 27 बड़े शहरों के लिए 17 भारतीय पंजीकृत कंपनियों को लाइसेंस जारी किये गए हैं। 18 दूरसंचार सर्किलों में 11 कंपनियों को 31 लाइसेंस प्रदान किये गये हैं।

जहां तक विलेज पब्लिक टेलीफोन (वीपीटी) का संबंध है, यह उल्लेख किया जाता है कि बुनियादी टेलीपोन सेवा में निविदा/लाइसेंस की शर्त के अनुसार, बुनियादी टेलीफोन सेवा प्रदान करने वाली लाइसेंसधारक कंपनी के लिए लाइसेंस अवधि के पहले तीन वर्षों में तिमाही आधार पर सीधी एक्सचेंज लाइनों की कम से कम 10 प्रतिशत लाइनें वीपीटी के लिए प्रदान करनी अपेक्षित है।

किसी भी मूल्यवर्धित सेवा लाइसेंस/रेडियों

पेजिंग सेवा में ग्रामीण क्षेत्र कवर करने की कोई अनिवार्य शर्त नहीं है।

डाक विभाग:

(ङ) ग्रामीण क्षेत्र में डाक सेवा को, डाक नेटवर्क के विस्तार, मनीआर्डर का उपग्रह के माध्यम से पारेषण द्वारा तथा वितरण प्रणालियों में सुधार लाकर सुदृढ़ बनाया जाना है।

दूरसंचार विभाग:

(ङ) सर्किलों में बुनियादी सेवाओं के लिए 6 दूरसंचार सर्किलों के लिए लाइसेंस करार पर हस्ताक्षर किये गए हैं। योजनावधि के दौरान निजी आपरेटरों द्वारा इन सर्किलों में लगभग 68,000 गावों को सेवा प्रदान करने की संभावना है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

(i) आंध्र प्रदेश सर्किल	:6222
(ii) गुजरात सर्किल	:4202
(iii) मध्य प्रदेशप्रथम वर्ष	:5500
सर्किल – द्वितीय वर्ष	:5500
तृतीय वर्ष	:3000

(अनंतिम)